

[श्री देवराव पाटील]

काटन कारपोरेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस सम्बन्ध में जो स्कीम बनाई है, उसके लिए केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे सकती और नतीजा यह हुआ कि डिफर्ड पेमेंट शुरू कर दिया। मैं माननीय मंत्री जो से नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो मोनोपली प्रोक्योरमेंट स्कीम चला रखी है, उसके मुताबिक गैरटोड प्राइस का 30 परसेंट दाम वह किसानों को उनके कपास का एडवॉन्स कर देती है और बाकी 70 परसेंट पैसा 30 जून तक देना होता है। इस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 30 जून तक सब किसानों को उनकी कपास का पूरा पैसा देना होगा। कामर्स मिनिस्टर साहब को यह बात अच्छी तरह से मालूम होगा। इसलिए मैं आपको मारफ़्त वित्त मंत्री जो से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मोनोपली प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, तो इससे किसानों को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी परेशानी होगी। सरकार का यह कहना गलत है कि अगर कपास के खरीदने के लिए पैसा दे दिया जायगा तो इससे इन्फ़्लेशन बढ़ जायगा। लेकिन यह तो केवल दो महीने की बात है और दो महीने के बाद तो सरकार को सब पैसा वापस मिल जाने वाला है और साथ ही उसमें व्याज भी मिलेगा। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि सरकार को इस कार्य के लिए महाराष्ट्र सरकार को पैसा अवश्य दे देना चाहिए।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA:
Sir,...

SHRI RAJNARAIN: Don't repeat the same.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: The questions are being repeated. What can I say? Sir, honestly speaking, the advice of Mr. Rajnarain is absolutely acceptable to me. What I will be saying, I will be repeating.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I hope he maintains the same attitude when he is involved.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Only I will say that the Agricultural Prices Commission every year fixes the price...

SHRI BHUPESH GUPTA: At least once Mr. Rajnarain has given a sensible advice and in an equally sensible way, you have accepted it.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): It applies to you also.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: This price is suggested by the Agricultural Prices Commission, an expert body, consisting of economists and agricultural experts, etc. Therefore, the Government is bound to accept...

(Interruption)

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: They have no experience.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I do not like to comment on their competence. They have their own views. The Government has formed the body, taking the best available people. Also records show that from year to year price is upwardly revised. That also indicates that the Government is alive to the increasing cost of production of cotton. But because of the dear money policy, Government has no alternative, but to cut down its credit accommodation for the CCI. This is not only for CCI, but for many other similar Corporations which could not be given the credit quantity which they had been getting in the last few years. This overall constraint has affected all sections of industry and some sections of trade, except the food trade. But Government has no other alternative left before it.

REFERENCE TO ILLTREATMENT OF HARIJANS

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, इस सदन में सत्ताधारी दल की ओर से हरिजनों के संबंध में घड़ियाल के आंसू बहुत बहाये जाते हैं मगर जब देखिए तो सत्ताधारी दल की ओर से ही उन पर प्रहार होता है। अभी-अभी मेरे पास कल बहुत से हरिजन नेता आये थे। यह थाना कैथल, जिला कुश्नौर, गांव मोहना के हरिजनों के साथ

वहाँ के तमाम प्रमुख लोग और वहाँ की पुलिस मिल कर उन पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं और वहाँ एक थानेदार है ओम प्रकाश तलवार, वह नाना प्रकार के अत्याचार करता है। वहाँ के श्री केहर सिंह जो हरिजन नेता हैं वह कल मझसे मिले थे उनका कहना है कि 65 आदिमियों को वहाँ बुरी तरह से पीटा गया है और उन को गिरफ्तार कर क जलम बंद कर दिया गया है। हरिजनों की सारी कोसी औरते इस समय अपने घरों से निकल रहे हैं और वह निकल कर दोपहरी में खेतों पर पड़ी रहती है और वह इस लिये अपने खेतों पर पड़ी रहती है कि उन के खेतों पर वह लोग मजदूरी डंग से अपना कबजा करना चाहते हैं। उस के बाद भी वहाँ पुलिस जाती है और उन हरिजनों को औरतों को घसीटती है और ट्रैक्टर चलवा कर वहाँ के सरमायेदार लोग उन खेतों को जोतने की कोशिश करते हैं और उन पर अपना कबजा दिखाना चाहते हैं। जब वह लोग हट जाते हैं और ट्रैक्टर आदि चले जाते हैं तो फिर वह आरते वहाँ जा कर लेट जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ने विशेष अनुकंपा की है कि मुझे यह प्रश्न यहाँ उठाने की अनुमति दी। एक हरियाणा के प्रान्तदध हरिजन नेता है और वहाँ के वधायक भी है चौधरी चांद राम उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है और वह चिट्ठी 8 मई की है। उस में उन्होंने कहा है कि वहाँ हरिजनों के साथ इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। उन्होंने उस में एक व्यक्ति का नाम भी बताया है। मैं जानता नहीं कि उस सब में उनका हाथ है या नहीं, लेकिन यदि उनका हाथ इस सब में है तो मुझे दुःख है इस लिये खास कर कि वह स्वयं राज्य सभा के सदस्यों है। चौधरी चांद राम जी, मैं नाम लिखा है श्री सुलतान सिंह एम० पी० का। मैं इस लिये कह रहा हूँ कि मैं ने इस की जांच नहीं की है। अगर श्री सुलतान सिंह, एम० पी० का इस में हाथ है तो वह इस में से

अपने हाथ को खींचे और वह वहाँ के हरिजनों की मदद करें न कि वहाँ के आततायियों की मदद करें या वहाँ के सरमायेदारों की मदद करें। मैं उनसे इतना ही निवेदन करूँगा और शासन से बहुत तो नहीं कहूँगा क्योंकि इस समय हरिजनों पर तो चारों तरफ से आफत आ रही है। आप समाचार पत्रों में देखेंगे कि कहीं न कहीं, किसी गांव में, किसी जिले में, किसी शहर में कहीं हरिजनों की जिन्दा जलाया जा रहा है या उनके घरों को उखाड़ कर फेंक दिया जा रहा है। यह सब अत्याचार उन पर बराबर किये जा रहे हैं। तो इस लिये मैं थोड़ेसे शब्दों में आप के द्वारा ओम् मेहता जी से विशेष तौर से कहूँगा कि इस मामले पर वह ध्यान में क्योंकि यह उन के दल के लोगों का काम है। यह दिल्ली की नाक के नीचे सब हो रहा है। तो कम से कम यहाँ वह ऐसा न होंगे दें।

REFERENCE TO DUMPING OF BOOKS WORTH CRORES OF RUPEES WITH N.B.T.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब इस प्रश्न को उठाना चाहता हूँ तो सीमाग्य से शिक्षा मंत्री प्रो० नुरुल हसन साहब यहाँ मौजूद हैं। उन के मंत्रालय से संबंधित धन का दुरुपयोग किस प्रकार से हो रहा है और किस तरह से करोड़ों रुपयों की पुस्तकें आज गोदामों में बीमकों का आहार बनने जा रही हैं इसकी ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मार्च के महीने में इस प्रकार का एक प्रश्न आया था जिस में पूछा गया था कि क्या शिक्षा मंत्रालय से संबंधित जो चार संगठन हैं जिन में एक सेंट्रल हिन्दी डाइरेक्टोरेट है, दूसरा नेशनल बुक ट्रस्ट है, तीसरा साहित्य अकादमी और चौथा ललित अकादमी है, उनके गोदामों में कितने रुपयों की पुस्तकें पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने स्वयं 5 मार्च को उत्तर देते ए बताया